पहाड़ी, सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के संवर्धन हेतु लाई गई परिवहन सहायता योजना के अधीन निर्धारित रेलवे केंद्रों/बंदरगाहों से औद्योगिक यूनिट स्थल तक इसके विपरीत कच्चे एवं तैयार माल की ढुलाई पर हुए व्यय पर 50% से 90% तक की सहायता अनुमन्य है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चलाई गई पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अनुमोदित वृद्धि केंद्रों में स्थित औद्योगिक यूनिटों को संयत्र एवं मशीनरी में उनके द्वारा किए गए निवेश के 15% तक सब्सिडी देय है। जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपने स्कीमों के तहत दुर्गम क्षेत्रों जिनमें जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना वाले क्षेत्र शामिल हैं, में स्थित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम के सैक्शन 80-1ए के तहत उपलब्ध दोहरे राजकोषीय प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए हरियाणा का कोई भी जिला औद्योगिक रुप से पिछड़े हुए जिले की श्रेणी में नहीं आता।

Constitution of Ocean Commission

3295. SHRI VAYALAR RAVI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of a proposal of constituting an Ocean Commission;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reasons for delay in constituting the Ocean Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) to (c) Ocean Commission is the fourth entry in the Allocation of Business Rules of the Department of Ocean Development. In 1997, a proposal was mooted regarding setting up of an Ocean Commission. A comprehensive paper containing details like Department's vision for ocean development, the proposed constitution, role, functions and powers of the Commission with an action plan for the next ten years requires to be prepared. The Department has already initiated the requisite action for preparation of a detailed proposal.

Laboratories under Department of Ocean Development

3296. SHRI VAYALAR RAVI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many laboratories are working under the Department of Ocean De velopment;

(b) whether it is a fact that certain Research Laboratories 'of Oceanography studies are working under different Ministries; and

(c) if so, what are the reasons for keeping these laboratories under different administrative control and how far it affects the research on ocean development activity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) There are no laboratories presently under the administrative control of the Department of Ocean Development. The Department, however, has set up the National Institute of Ocean Technology, a registered Society under its administrative control in November, 1993 at Chennai and the Antarctic Study Centre another registered society at Goa in May, 1998. These in due course will have some laboratories.

(b) Yes, Sir.

(c) Department of Ocean Development (DOD) was created in 1981 and by that time many Government of India Dcpart-mcntyMinistries which were having ocean related activities had set up institutions^

facilities to undertake those activities. As per the Allocation of Business Rules, the DOD is to handle "any other activity npt specifically allocated to any other Ministry or Department". Ocean related activities are by and large multi-disciplinary and multi-institution in nature and therefore, the Department has been utilising the facilities already set up for various ocean related activities by various De-partnientyMinistries.

Transfer of National Institute of Oceanography

3297. SHRl VAYALAR RAVI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Institute of Oceanography is still under the CSIR;

(b) whether the Department of Ocean Development require this institute; and

(c) if so, the steps taken to transfer the National Institute of Oceanography to the Department of Ocean Development for research activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE REVENUE (BANKING, AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Yes, Sir. A proposal for transfer of National Institute of Oceanography to the Department of Ocean Development has been made. Decision is yet to be taken.

ज्वारीय तरंगों से विद्युत उत्पादन

3298. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ज्वारीत तरंगों से विद्युत पैदा की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के लम्बे समुद्र तट को ध्यान में रखते हुए सरकार ज्वारीत तरंगों से विद्युत उत्पन्न करने की तकनीक विकसित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) महासागर विकास विभाग के अनतर्गत राष्ट्रीय समुद्र का विदोहन करने वाली विकास परियोजनाओं में संलग्न है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान में तरंग ऊर्जा समूह तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई दोलायमान जल स्तंभ सहिस तरंगों से प्रौद्योगिकी विकास और कूप टरबाइन सहित विद्युत मापाक पर कार्य कर रहा है। केरल में त्रिवेन्द्रम के समीप विझीजम में 1991 में 23.2 मी.x17 मी. X 15.3 मी. परिमाप सहित एक दोलायमान जल स्तंभ, केसन की स्थापना की गई थी जिसके विद्युत मापक की क्षमता 10 किलोवाट है, और इस प्रणाली के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। तदन्तर दोहरे टरबाइन वाले 5 किलोवाट क्षमता के एक विद्युत मापक और एक केन्द्रीय जनित्र का विकास किया गया और इस प्रणाली के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन 1996 में किया गया। बाद में 1997 में उक्त विद्युत मापाक को इष्टतमीकृत किया गया और स्वप्रक्षेपित निर्देशक फलक युक्त अभिप्रेरण टरबाइन जो संपर्कों से जुड़ा होता है, का अभिकल्पन, संचालन और मूल्यांकन किया गया। इससे 80 किलोवाट तक विद्युत उत्पादन की वृद्धि हुई। संतरण पश्चनत नलिकायुक्त प्लव यत्र सहित तरंग विद्युत मापाक के अभिकल्पन का कार्य आरंभ किया जाता है। इन प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विद्युत के सुदूर स्त्रोत के रुप में एक आदर्श तरंग विद्युत मार्ग निर्देशी प्लव यंत्र विकसित किए जाने की योजना है।

ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावना तलाशने के उद्देश्य से, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एम. एन. ई. एस.) ने पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन में दुर्मादुनेई सकरी खाड़ी में लधु ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन किए। आवश्यक क्षेत्र अध्ययनों एवं कम्प्यूटर प्रतिरुपण अभ्यासों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 3 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से इस स्थान पर प्रति वर्ष 5.5 मिलियन किलोवाट हर्टज ऊर्जा का उत्पादन संभव होगा। अपरंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सहयोग से पश्चिम